[Mr. Dututy Chairman]

minute, it is my request. ...(*Interruptions*)... My request is, give me one minute. ...(*Interruptions*)... It is my request. ...(*Interruptions*)... I want to convey something ...(*Interruptions*)... I will be forced to take action. ...(*Interruptions*).. I am requesting you to go back. ...(*Interruptions*)... Okay. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, under the authority conferred on me by Rule 255 for Rules of Procedure and Conduct of Business of the House, I am hereby invoking Rule 255 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Council of States, and under that authority, I am directing Mr. Chowdary and Mr. Ramesh to leave the House immediately. ...(*Interruptions*).. Please vacate. ...(*Interruptions*)... I am asking you, 'vacate'. ...(*Interruptions*).. The House is adjourned for thirty minutes.

The House then adjourned at fifty-six minutes past two of the clock.

The House re-assembled at twenty-six minutes past three of the clock,

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

GOVERNMENT BILLS--Contd.

The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up further consideration of The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010. The other day, we had decided to give a maximum of one hour only to this Bill. Now, Dr. Najma A. Heptulla.

एक माननीय सदस्य: एक घंटा तो बहुत कम है। ...(**व्यवधान**)...

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): आप बोलेंगे, तो मंत्री जी इस को बढ़ा देंगे। ...(**व्यवधान**)... वे ज्यादा टाइम के लिए अलाउ कर देंगे और डिप्टी चेयर मैन साहब भी बढ़ा देंगे। सर, जो पहला बिल आया था, उस पर हम सब लोग बोल चुके हैं। अब मंत्री जी इस लेजिस्लेशन को आठ अमेंडमेंट्स के साथ दोबारा इस हाउस में लेकर आए हैं, जब से मंत्री जी

इस लेजिस्लेशन को अमेंडमेंट के साथ लेकर आए हैं, तब से इन चार-पांच दिनों में मुझे कम से कम 400-500 मैसेज, एसएमएस और ईमेल के रूप में आए हैं। मंत्री जी, हम यदि कोई भी लेजिस्लेशन आते हैं, तो उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे देश में, हमारी सभ्यता में और हमारे कल्चर में मैरिज की कोई वैल्यू है। हम लोग मैरिज को अहमियत देते हैं, फैमिली को अहमियत देते हैं, उसकी यूनिटी को अहमियत देते हैं। भारत की सभ्यता और कल्चर divorce is a taboo, हमारे यहां इसे लग्ज़री नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक तरह से मजबूरी माना जाता है। यह मजबूरी तब है जब फैमिली नहीं चल पाती। लोग साथ नहीं रह पाते, तो यह मजबूरी हो जाती है, इसलिए डिवोर्स का सहारा लिया जाता है। कोई लड़का या लड़की खुशी से डिवोर्स नहीं लेता। मैं दोनों की बात करूंगी, मैं समानता की बात करूंगी, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे कांस्टिटच्यूशन में पुरूष और स्त्री बराबर हैं। फैमिली में दोनों का हक़ बराबर है। अगर कहीं असमानता है, तो वहां हम समानता लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कांस्टिटच्यूशन में पॉज़िटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है, जहां तक महिलाओं का सवाल है।

(उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) पीठासीन हुए)

मंत्री जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगी। अगर किसी को समाज में ऐसा लग रहा है, खास तौर पर पुरूषों को, हालांकि कुछ महिलाओं ने भी मुझे फोन किया और वे आकर मुझ से मिली, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके इन आठ नए अमेंडमेंट्स में से किसी अमेंडमेंट की वजह से असमानता पैदा होगी, किसी के साथ अन्याय होगा, तो मैं समझती हूं कि यह सही नहीं है और आप इस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि कोशिश यही करनी चाहिए कि फैमिली स्ट्रक्चर न टूटे। हम वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन से अपने आपको कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। उनका माहौल दूसरा हे, उनके यहां का रहन-सहन अलग है और वे इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि हमारा समाज इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं सिर्फ़ एक बात आपके सामने कहना चाहती हूं कि इस बिल से आपने कुछ लोगों के साथ अन्याय किया है। हम वहां ओथ लेते हैं, आपने भी ओथ ली। आप तो लॉ मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। जब आप यहां बैठते थे तो बहुत अच्छा बोलते थे, वहां बैठते है तो अच्छा बोलते हैं, अच्छे मंत्री हैं और बहुत अच्छे लॉयर हैं, काबिल लॉयर हैं। हम यहां संविधान की, हमारे कंस्टीटच्यूशन की, हमारे आईन की ओथ लेते हैं कि हम अपने आईन का पालन करेंगे। जो ओथ हमने यहां ली है उस पर अमल करेंगे और कोशिश यह करेंगे कि हम गलती से भी अपने लाईन के खिलाफ न बोलें, लेकिन मुझे एक शिकायत है। हमारे प्रिएम्बल में लिखा है कि equal opportunities, equality की बात हो। आपको तो कानून पढ़कर सुनाने की

[डा. नजमा ए. हेपतुल्ला]

जरूरत नहीं है, आपको तो कंस्टीट्यूशन जुबानी याद होगा, मुझे तो बार-बार पढ़ना पड़ता है। जस्टिस की बात की गई तो, सबसे पहला है जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी। इस देश की 100 मिलियन, 10 करोड़ महिलाओं के हक के बारे में आपने नहीं सोचा। मुझे आज इस बात पर बड़ी खुशी है कि आप ऐसा कानून लाए हैं कि मेरी बहनों की जो समस्याएं है, उनका समाधान होगा। उम्मीद है कि इसका इम्प्लीमेंटस अच्छा होगा। मगर मंत्री जी, इस देश में और भी महिलाएं हैं। कम से कम 100 मिलियन तो हैं, अगर मेरी गिनती गलत नहीं है, तो इससे कुछ ज्यादा ही हैं, जिनके बारे में इस बिल के कोई जिक्र नहीं है। मैं मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हूं। इस हाउस में हम तीन मुस्लिम महिलाएं हैं, दो उधर, मोहसिना जी और नाज़नीन जी और मैं इधर अकेली, शायद मेरी पार्टी में मैं अकेली हूं। लोक सभा में कांग्रेसी मुस्लिम महिलाएं होंगी, मुझे पता नहीं है। इतनी मालूमात नहीं की कि वहां कितनी हैं, क्योंकि मैं हिन्दू-मुसलमान की गिनती कभी करती नहीं हूं। मैं सिर्फ महिला की गिनती करती हूं। मगर मुझे यह लगा कि इतने सालों में आपने यह नहीं सोचा। कानून तो बार-बार आता है। हिन्दू मैरिज एक्ट का, स्पेशल मैरिज ऐक्ट का, मगर इसमें आप बांट क्यों रहे हो? आपको नहीं लगता कि आप 10 करोड़ महिलाओं के हित की हिफाजत नहीं कर रहे हैं? क्या हम उन्हें इक्वल अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं? क्या हम अपने कंस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के खिलाफ जा रहे हैं? उनको हक नहीं देकर क्या हमारे आईन का, हमारे कंस्टीट्यूशन का, हमारे संविधान का हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी जरूरत है? उनके यहां भी तलाक होता है, उनके बच्चे रगड़ जाते हैं मुम्बई की जुबान में, कि उनका कोई वाली-वारिस नहीं होता। पढ़ने की उनको तकलीफ होती है, रोटी खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। मंत्री जी, आप क्यों नहीं उनके लिए बिल लेकर आए? मुझे याद है यहां इस हाउस में जब भी बात होती है, कभी हाउस के अंदर जिक्र होता है, तो कहा जाता है कि यह कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, इसलिए कोई भी जवाब दे सकता है। अगर आप पुराना इतिहास देखें तो अशोक सेन साहब, जो एक बड़े अच्छे वकील थे आप मानते होंगे, उन्होंने इस सदन में कई वायदे किए थे, जब शहबानो केस पर बिल आया था। उन्होंने कई प्रॉमिसेज किए थे कि हम जरूर उसमें तब्दीली लाएंगे। आज कितने साल हो गए हैं, क्या कोई तब्दीली हुई? मैं यकीनन यहां अकेली बैठी हूं, लेकिन मैं यह जिम्मेदारी से कह सकती हूं कि मेरे भाई और मेरी बहनें, जो मेरे साथ बैठे हैं और लोक सभा में हैं, वे सब मेरे साथ इस बात पर सहमत थे कि हिन्दुस्तान की 100 मिलियन मुसलमान औरतों के बारे में यह सरकार कुछ सोचती नहीं है। उनके बारे एक लेजिस्लेशन भी कभी लेकर नहीं आए। अनकी फलाहों बेहबूदी, उनकी बेहतरी के लिए आपने कभी कोई काम नहीं किया। मंत्री जी, आपकी कंस्टीट्यूंसी में तो वे लोग मजॉरिटी में हैं, काफी तादाद में हैं। क्या आपको उनका कभी ख्याल नहीं आता कि मुसलमान

औरतों के लिए भी हमें कुछ करना है? क्या आपको लगता है कि सभी मुसलमान मर्द बहुत अच्छे होते हैं? क्या मुसलमान औरतों के लिए आपको नहीं बोलना चाहिए? क्या वे इस देश की नागरिक नहीं हैं? आप सब लोग खामोश बैठे हैं, कोई एक तो खड़ा होकर बोले कि हां, हम समझते हैं कि यह गलत है। क्या पाबंदी है आपके ऊपर? क्या आप मेजॉरिटी महिलाओं की बात कर रहे हैं? एक मायनॉरिटी के लिए बोलने को कोई खड़ा नहीं होता। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए, मैं बहुत खुश होऊंगी।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): I am sorry, Najma ji. If you yield for a minute. ...(*Interruptions*)... I am speaking for myself as well. There is no question of our looking at any woman, irrespective of which community or caste they belong to, in any way different from what we see ourselves. Women are fifty per cent of this country's population and there is no question of further dividing them or seeing that their needs are not met. So, there is no question of our not speaking for them. Let me tell you, cutting across all lines, we have always stood and spoken for women, particularly, for minority community women. They are our sisters, and, so, the question of not speaking for them does not arise.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Renuka ji, if you want to intervene here, you can do that. ...(*Interruptions*)... Dr. Najma, you please carry on.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I allowed her to speak. I mean, if it is from my time, I don't mind because I am very happy, at least, one woman got up from the other side.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have three minutes more.

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला: सर, आप महिलाओं के मामले में इतना अत्याचार कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भूवनेश्वर कालिता): आप अपना टाइम भी उन्हें दे रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला: सर, दे दीजिए। देखिए, इस हाउस से हम कोई ऐसा गलत लेजिस्लेशन पास करें, जिसका हजारों, लाखों करोड़ों लोगों पर असर पड़े और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, तो यह बड़े अफसोस की बात होगी। क्या महिलाओं के विषय पर बात करने के लिए ऐसा कर के हम मुंह दिखा सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं था? क्या हम कह सकते हैं कि हमने जल्दी-जल्दी बिल पास कर दिया, जिसका इफैक्ट फैमिलीज पर पड़ने वाला है, जिसका इफैक्ट लाखों-करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है? इस मुल्क

[डा. नजमा ए. हेपतुल्ला]

में 49 परसेंट महिलाएं हैं और उन 49 परसेंट में 100 मिलियम मुसलमान औरतें हैं, जिन के बारे में इस सरकार ने कभी एक लफ्ज नहीं कहा, जिन के बारे में कभी एक आवाज नहीं उठाई। यहां के. रहमान खान साहब बैठे हैं, जो मायनॉरिटीज डिपाअर्मेंट के मंत्री हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Madam, you please address the Chair.

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला: मैं आपके थ्रू उनसे पूछना चाहती हूं, I agree with you. क्या आप कभी कोई लेजिस्लेशन लेकर आए? शहवानों केस के बाद कोई रिफॉर्म्स किए? उनकी बेहतरी के लिए कुछ सोचा कि उनकी भी कुछ समस्याएं हैं? यह किसी ने नहीं सोचा क्योंकि खाली वोट की पॉजिटिक्स होती है। बोट के लिए, फिर तुम जेहन्नुम में जाओ। तुम्हारी औरतें और मर्दों की हमें कोई परवाह नहीं। सर, अगर यह सरकार कोई लेजिस्लेशन मुस्लिम महिलाओं के लिए लेकर आती हैं, तो मेरी पार्टी के सब लोग मेरे पीछे खड़े रहेंगे। मैं आपको वायदा करती हूं कि सब आपको सपोर्ट करेंगे, कोई अपोज़ नहीं करेगा, लेकिन आप लेकर तो आइए। आप कोशिश ही नहीं करते। हमारी रेणुका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि औरतों को डिवाइड नहीं किजिए। मैं भी यही कहना चाहती हूं कि औरतों के लिए एक लॉ होना चाहिए। अगर मेरी तीन लड़कियां हैं, एक लड़की अगर मुसलमान से शादी करती है, तो उसके लिए एक कानून है, मेरी दूसरी लड़की अगर हिंदू से शादी करती है, तो उसके लिए दूसरा कानून है, अगर मेरी लड़की पारसी से शादी करती है, तो उसके लिए तीसरा कानून है। क्या आप औरतों को इस तरह कानूनों से बांट देंगे? एक घर की तीन लड़कियों को आप हिस्सों में बांट दोगे? यह कोई इंसाफ है? क्या आप नहीं समझते कि आप अपने संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? Are you giving equal opportunity to the three women in one family? What kind of law is it? मंत्री जी, आप सुन लीजिए। उन्हें बाद में ब्रीफ कर दीजिए।

कानून एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैडम, हमें जूनियर भी ब्रीफ करता है और कोर्ट भी बातें करती है और हम दोनों को सुनते हैं।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला: ठीक है, आपके दो कान हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने दोनों कानों से अलग-अलग बात सुन लेते हैं, लेकिन मेरी बात को इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत दीजिएगा। सर, मैं अहमियत की बात कर रही थी। आपको भी जवाब देना है। यह अदालत और यह पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, हम लोग यहां से रिटायर होकर चले जाएंगे, दुनिया से भी रिटायर होकर चले जाएंगे, लेकिन एक बड़ी अदालत भी है, खुदा की अदालत। जब मुझसे कोई इस बारे में वहां पूछेगा तो मुझे भी वहां जवाब देना है। हमें बनाने वाले ने औरत और मर्द को बराबर बनाया। अगर मुझसे कोई वहां पूछेगा कि जब औरतों

के साथ यह नाइंसाफी हो रही थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि इतने बड़े सदन में बैठकर मैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकी? आप सुने या न सुने, आप अमल करें या न करें, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं उम्मीद करती हूं कि आप जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि आप मुस्लिम महिलाओं के बारे में इस बिल में क्या करेंगे। आप महिलाओं को नहीं बांटेंगे, आप महिलाओं के लिए एक ही कानून लाइए। आप यह वादा कीजिए कि आप महिलाओं के लिए एक ही कानून लेकर आएंगे। चाहे वह किसी भी धर्म की महिला हो, किसी भी मज़हब को मानती हो, आप सबके लिए एक कानून लाइए, one law for all the women of the country. Thank you.

डा. राम प्रकाश (हरियाणा): सम्मानीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह वह देश है, जिसने कभी "वसुधैव कुटुम्बकम्" का नारा दिया था। उस देश में सांझे परिवार की इकाई टूट गयी और आज एकल परिवार भी टूट रहा है। इसलिए आज इस बात की जरूरत पैदा हुई है कि अगर विवाह सही तौर पर नहीं चल रहा है तो उसे खत्म होने की इजाज़त होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। यह परिवारिक समस्या हमारे पाश्चात्य चिंतन से जन्म लेती है। हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि पश्चिम एक ऐसी दिशा है, जहां जाकर सूरज भी डूब जाता है। हम अगर उसका अंधा अनुकरण करेंगे तो हमारी स्थिति भी उससे बेहतर नहीं होगी। यह परिवार इसलिए टूटा कि हमारी सोच में एक सुधार करने की आवश्यकता है। हम यह तो चाहे है कि वह घर में बेटी बनकर रहे, लेकिन हमने कभी उसे बेटी नहीं समझा। उसकी वजह से उसके साथ दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर कांच का गिलास रास्ते में पड़ा है, उसे ठोकर लगती है, तो वह टूट जाता है। अगर वह बेटी से टूटता है तो मां कहती हैं, पांव में चोट तो नहीं लगी, लेकिन अगर वही गिलास बहू से टूट जाता है तो कहती है, अंधी हो रही है, सारे बर्तन इसी तरह तोड़ेगी? यह सोच का फर्क है, जिसकी वजह से आज हमारे सामने यह समस्या पैदा हुई है। अगर हम बहू को बेटी बनाना सीख जाएं तो शायद आज तलाक की जो समस्याएं हैं, वे आधी रह जाएंगी। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि जीवन तबाह नहीं होना चाहिए। आज हर महिला का, हर पुरुष का जीवन में कुछ पोटेंशियल है, उसका पूरा लाभ उसे मिल सके ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu) Sir, we are not able to hear. There is disturbance in the mike.

डा. राम प्रकाश: इसके लिए यह जरूरी है कि अगर विवाह ठीक नहीं चल रहा है तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। महोदय, यह समस्या इतनी ही नहीं है। आज दहेज के नाम पर विवाह टूटने के लाखों केस कचहरियों में पड़े हैं। बीस-बीस साल तक वे केस उलझे रह जाते हैं। वे एक दूसरे को सजा देने पर तुले होते हैं कि मेरी ज़िउगी तो तबाह हो गयी, अब इसकी ज़िदगी भी तबाह करूंगा। मैं यह समझता हूं कि अगर मंत्री जी इस बिल में इस

[डा. राम प्रकाश]

तरह का भी कोई प्रावधान कर पाएं कि जो बहुत लम्बे समय से तलाक के केस चल रहे हैं, उनको कोई समाधान हो पाए, तो शायद जो भाव हम लेकर चले हैं, उस भाव की गहराई के साथ पूर्ति हो सकेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो दहेज का कानून है, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। बूढ़ा बाप है, उसने हार्ट सर्जरी कराई है, लेकिन उसको जेल के अंदर डाला जा सकता है। बुढ़ी मां है, उसको भी तंग करने के लिए दहेज का केस बनाया जाता है। क्या बूढ़ी मां महिला नहीं है तो उसके साथ यह अत्याचार होता है? इसलिए जहां आप यह बिल लेकर आए हैं, वहीं इस समस्या की तरफ भी ध्यान दें। जो लम्बे समय से केस चल रहे हैं वे भी ऐसे विवाह हैं जो किसी भी तरह दोबारा ठीक नहीं हो पाएंगे, जो नहीं निभा पाएंगे। जो 20-20 साल में नहीं निभ पाए, तो अब हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? अगर हम इस बिल को पास करते हैं, जिसका मैं समर्थन करता हूं, तो हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का योगदान इस देश को दे सकते हैं, लेकिन उनकी कचहरियों के दरवाजे खटखटाते हुए सारी उम्र निकल जाती है।

मैं इस बारे में एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि तलाक दीजिए, लेकिन जो छोटे-छोटे बच्चे अपनी मां की तरफ देख रहे हैं, अपने पिता की तरफ देख रहे हैं, पति-पत्नी की आपस में नहीं निभा पाई, वे तो अपनी जिंदगी बसर करने के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभल कौन करेगा? यहां केवल आर्थिक संरक्षण की बात नहीं हैं, यहां भावनात्मक सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है। छोटे-छोटे बच्चों से अपनी मां छिन जाएगी या उनसे पिता छिन जाएगा, इस बारे में भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अपनी मैरिज को नाकामयाब मानकर विवाह तोड़ रहे हैं, उन्हें विवाह तोड़ने दीजिए, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसी कंडिशन भी होनी चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं, वे अनाथ बच्चे बनकर तड़पते हुए न रह जाएं बल्कि उनका भी कोई भविष्य हो, उनकी भी कोई जिन्दगी हो। वे भी अपना भविष्य देखते हैं, वे भी अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं।

मैं आपसे अगली बात यह कहना चाहूंगा कि मेट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में डिवोर्सड का हिस्सा है। आपने 50 परसेंट तक कर दिया, मुबारक हो, लेकिन जो छोटे-छोटे बच्चे पीछे रह गए जिनकी पढ़ाई-लिखाई होनी है, उनके लिए क्या हिस्सा है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहूंगा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एक गरीब लड़का है, जिसका पिता भूमिहीन है, उस पिता ने मजदूरी करके, पेट पर पत्थर बांधकर, धरती को बिछोना और आकाश को अपना ओढ़ना मानकर, अपने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद वह बच्चा अच्छा इंजीनियर बन गया, नौकरी पर लग गया। विवाह हुआ, लेकिन वह निभ नहीं पाया, उसका विवाह टूट गया। आधी प्रॉपर्टी उसके पास से चली गई, तो वह बुढ़े मां-बाप का क्या सहारा बनेगा? उसके जो छोटे भाई-बहन हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? जब हम कानून बनाते हैं, तो उसमें हमें इन सारे पहलुओं के बारे में विचार करना चाहिए कि जो छोटे

बच्चे हैं, उनका क्या होगा, जो डिपेंडेंट भाई और बहन हैं, उनका क्या होगा, जो डिपेंडेंट बूढ़े मां-बाप हैं, जिनकी कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, उनका क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। मेरी अगली बात को हंसी में मत लिजिएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बार 50 परसेंट प्रॉपर्टी मिल गई, उसने दूसरी बार तलाक पेश किया, तो फिर उसे 50 परसेंट मिलेगा। यहां तो ऐसे भी केस हैं जिन्होंने तीसरी बार तलाक लिया है। इसके बारे में हमें बिल में बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए। समाज में अच्छे लोग भी हैं और समाज में बुरे लोग भी हैं। अच्छी महिलाएं हैं, पूजा के काबिल हैं, देवियां हैं, मैं उन्हें श्रद्धपूर्वक नमन करता हूं, उनके पांव छूता हूं। जो अच्छे आदमी हैं, मैं सिर झुकाकर उनका अभिनन्दन करता हूं, लेकिन समाज में जहां राम हे, वहां रावण भी है। जब आप कोई कानूनी व्यवस्था कर रहे हैं तो इस बारे में भी कानूनी व्यवस्था करने की जरूरत है।

मैं आपसे एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं। आजकल हमारे गावों में इस तरह के केसेज़ हो रहे हैं। कोई विवाहित स्त्री है, उसके दो-तीन बच्चे हैं, वह घर में किसी को बताए बिना किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। मुझे यह भाषा मजबूरी में इस्तेमाल करनी पड़ रही है, मैं किसी देवी के बारे में ऐसे शब्द कहना नहीं चाहता हूं। उसने जाकर किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, उसने तलाक लिया नहीं, तो क्या मेट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का हक उसके लिए भी है, यह बात भी थोड़ी स्पष्टीकरण मांगती है। एक बात और है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है हिन्दुस्तान में जो सबसे ज्यादा दुखिया है, वह माइग्रेटरी लेबर की महिला है, चाहे वह भट्टे पर काम करती हो, चाहे वह कंस्ट्रक्शन का काम करती हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्डिंग में काम करती हुई एक महिला को, उसको देखकर आदमी को ऐसा लगता है कि इसमें सांस कहां से चल रही है? उसके साथ दो-तीन बच्चे थे। मैंने यह पूछा कि यह महिला मजदूरी क्यों करती है, इसके पति मजदूरी क्यों नहीं करते? मुझे कहा गया कि जब यह फलां प्रदेश से आई थी तब तो इसके साथ पति था, लेकिन वह तो इसे छोड़कर कहीं चला जएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या हमने कोई ऐसा सर्वे किया है? जो महिलाओं माइग्रेटरी लेबर इस तरह की असहाय, दुखिया और रोटी को मोहताज हैं तथा उनके साथ बच्चे हैं, क्या हम उनके लिए भी बिल में व्यवस्था करेंगे? ...(**समय की घंटी**)... आपका संकेत हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री नरेन्द्र कश्यप (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 का प्रभाव यकीनन देश की अधिकांश आबादी पर होगा। यह सदन इस मत का समर्थक है कि महिलाओं को देश में सशक्त रूप से आगे आना चाहिए। इस मत का समर्थन भारतीय संविधान के निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। जो देश के सबसे पहले कानून मंत्री बने थे और वे हिन्दु कोड बिल लेकर आए थे। हिन्दू कोड बिल के

[श्री नरेन्द्र कश्यप]

माध्यम से उन्होंने इस बात समर्थन किया था। चूंकि महिला देश के सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, इसलिए महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा की व्यवस्था देश की शासन प्रणाली को करनी चाहिए। देश की मौजूदा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की योजना को इस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि इससे पहले भी कई कानून हमारे देश में बने हैं, आईपीसी में संशोधन हुआ है, उसमें 498(a) जोड़ा गया है और एक नया दहेज अधिनियम 3/4 बनाया गया। सरकार की यह मंशा थी कि महिलाओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन आज देश के सियासी लोगों पर एक सवालिया निशान लगता है कि देश आजाद होने के बाद तथा प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रयोग के बाद भी हम महिलाओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, मैं इस बिल को दो भागों में बांटकर देखता हूं। इस बिल के पहले भाग पर हमारे देश के योग्य माननीय मंत्री जी ने डिवोर्स के सिस्टम में और विस्तार करने की कोशिश की है। हम आपके इस विस्तार-रूप से सहमत हैं। आपने म्यूचुअल डिवार्स के लिए तीन साल का समय निश्चित किया और बहुत से कानूनी प्रावधान भी दिए। हमें उन पर ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस बिल में एक चीज देखने को नहीं मिली कि अगर कोई महिला या व्यक्ति बहरा, गूंगा या अनपढ़ है और उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, इस बात का जिक्र पहले भी कानून-वेत्ताओं ने किया है, तो उनके लिए विवाह-विच्छेद की प्रणाली कैसे लागू होगी, कैसे वे अपने परिवारिक जीवन से आगे बढ़ सकेंगे?

दूसरी बात यह है ...(**समय की घंटी**)... कि आपने परिवारिक सम्पत्ति में पत्नी की हिस्सेदारी पर अपनी व्यवस्था दी है। यह देश की महिलाओं की एक बड़ी मांग थी। पूरा देश, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि सम्बन्ध विच्छेदन हो जाने के बाद महिलाओं को बेसहारा, असहाय न होना पड़े इसलिए पति की सम्पत्ति में से उसको हिस्सेदारी देने की व्यवस्था को हम एक अच्छे कानून की व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन उन सम्बन्धों से जन्में बच्चों का उस प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी का क्या प्रतिशत होगा, इस पर कानून मौन है, इस पर विधेयक में कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है। क्या माननीय मंत्री जी विवाह से उत्पन्न ऐसे बच्चों के जीवन-भरण के लिए विवाह-विच्छेद के उपरांत पिता की सम्पत्ति में हिस्सेदारी में प्रतिशत तय करने पर भी विचार करेंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): समाप्त कीजिए। आपका समय पूरा हो चुका है।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: महोदय, मुझे मालूम है कि समय की कमी है, लेकिन यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के भारतीय युग में बहुत सारे पुरुष अपनी सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन पत्नी के नाम भी कराते हैं, लेकिन अगर पति के पास जीवन गुजारने की व्यवस्था नहीं है और सम्पत्ति की मालिक भी पत्नी है, तो क्या उस सूरत में यह कानून पति को भी पत्नी की

सम्पत्ति में से कानूनी हक़ लेने का अधिकार दे सकेगा? यदि मंत्री जी इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): समाप्त कीजिए, आपका समय पूरा हो चुका है।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी स्पीच समाप्त कर रहा हूं। शायद आपने इस विल के प्रभाव को हिंदू धर्म से जुड़े परिवारों तक सीमित रखा है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या डाइवोर्स के बाद जो बाकी मज़हब के लोग हैं, उनकी महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सेदारी का कानूनी हक़ मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि मंत्री जी इस पर भी कोई व्यवस्था देंगे, तो मैं समझता हूं कि इस देश की शत-प्रतिशत महिलाओं का जीवन विवाह विच्छेद के बाद सुरक्षित हो जाएगा और आपके इस अधिनियम की महत्ता बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी आप अच्छा कानून लाए हैं, आपने एक अच्छी शुरूआत की है और उपसभाध्यक्ष जी ने इस पर बोलने का मौका दिया है, इसलिए, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010.

Sir, we are moving an amendment to the official amendment proposed by the hon. Minister in clause 13F. We demand that this clause be deleted, and a new clause should be added. The official amendment is to give equal share in the immovable property (other than inherited or, inheritable immovable property) which is acquired during the subsistence of the marriage; and court will decide how much share is to be given. But our amendment is that the property acquired during the subsistence of marriage be divided equally between the husband and wife because of the three reasons. First, equal share on the property is a woman's right. Second, leaving the decision to court to fix the quantum of the share that should be given to the women would create adverse effects, since many courts are manned by persons who have patriarchal mindset and represent the male-dominated value system of our society. Third, by clubbing the share of wife and children together, the equal share of the wife gets reduced. इस बिल के आने के बाद हम लोग यह देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे एस.एम.एस. आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये मेल ग्रुप्स से आ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर यह बिल पास होगा तो फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं इस हाउस में यह पूछना चाहती हूं कि महिला के पास क्या है? महिला से यह कहा जाता है, उसको यह सम्मान दिया जाता है, यह माना जाता है कि वह आधा आसमान है, आधा आकाश है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हम लोग यह नहीं चाहते हैं।

[Shrimati Jharna Das Baidya]

1.00 P.M.

हम लोग आकाश नहीं चाहते, आकाश तो इतनी दूर है। हम लोग जमीन चाहते हैं। हम लोग जमीन मांगते हैं। एक महिला को जमीन क्यों नहीं दी जाएगी?

महोदय, डिवोर्स की बात आती है। कोई भी महिला ऐसे ही डिवार्स नहीं चाहती है। जब घटनाएं होती है, तब वह डिवोर्स मांगती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं वह बताना चाहती हूं। The Supreme Court of India has observed, "The Government should assess the value of the unpaid homemaker both in accident claims and in matters of division of matrimonial properties". The Court has also stated, "Parliament should make amendments to matrimonial laws to give effect to the mandate of Article 15(1) of the Constitution". (**समय की घंटी**)

सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रही हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि डिवोर्स में ईक्वल शेयर होना चाहिए। अगर ईक्वल शेयर नहीं होगा, तो we will move the amendments for equal share as we cannot be party to liberalization of divorce laws without necessary protection of women and safeguarding of their equal rights. Thank you.

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, there is an old saying which says, 'If you marry in haste, you repent in leisure'. Sir, you have given me only two minutes today; so I better make my points in haste, but make two very quick points before you ring the bell.

Firstly, I want to appreciate the Minister for including those amendments which were solely lacking in the original Bill, particularly, the one about inheritance and inheritable immovable property, and, of course, the other one about minor children. And now the adopted children are also included in that. These are very nice two-three amendments. I know it is a little bit of fait accompli because the Government and the leading Opposition Party have got together, so this is going to pass in any case, but we must flag this point, Sir. The point is, this is a wonderful idea to empower women and we are all for that, but while empowering women, why leave the men out? Our focus is, keep empowering women, especially in a country like India where women are empowered in so many different ways. But make it a gender-neutral approach. Replace the word 'wife or husband' with 'spouse'. This is

one point because as much as we want to empower women, we must empower women, but why should we empower women at the expense of men? Both can be empowered, and I know in 99 per cent of cases, it is the woman who is given the bad deal, but in those one or two per cent cases, if it is gender-neutral, if it is more forward-thinking, and if it takes a view that there is a lot of good thinking, which has happened in this Bill, including the amendments, so if that one more step is taken in the future, that would be even better; more power to women. Thank you.

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे हिन्दू विवाह अधिनियम पर बोलने का मौका दिया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह प्रमुख संस्कारों में से एक है। प्राय: यह भी कहा जाता है कि ये ऐसे रिश्ते होते हैं, जो जन्म लेने से पूर्व ही भगवान के घर में निश्चित हो जाते हैं। समाज में तमाम विकृतियां हैं। जिस तरह से स्वस्थ शरीर में बीमारी प्रवेश कर जाती है, उसी तरीके से स्वस्थ वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट प्रवेश कर जाती है। मंत्री जी हमने आपके बिल को बहुत ध्यान से पढ़ा है। विवाह विच्छेद के बाद पत्नी अपना जीवनयापन ठीक से कर सके, इसके लिए नियम कानून अवश्य बनने चाहिए।

महोदय, आपने इसमें यह दिया है कि विवाह विच्छेद के बाद पति की अर्जित सम्पत्ति में पत्नी का हिस्सा होगा। गुजारा भत्ता कितना होगा, अदालत यह बाद में तय करेगी। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि पति-पत्नी के बीच जो तलाक होता है, उसके लिए केवल पति जिम्मेदार होता है। इस संशोधन से यह स्पष्ट हुआ है कि तलाक के लिए पूर्णत: पति को जिम्मेदार ठहराया गया है। ...(**समय की घंटी**)...

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि पत्नी नौकरी कर रही हो और उसने तलाक की अर्जी डाली हो, पति बेरोज़गार हो, तो क्या ऐसी स्थिति में तलाकशुदा पत्नी अपने बेरोज़गार पति को गुजारा भत्ता देगी? क्या इस बिल में यह व्यवस्था है? तमाम लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं और लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या यह कानून पूरे तरीके से गुलाम बनाने के लिए है?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अरविन्द कुमार सिंह: महोदय, इतना ही नहीं, सदन ने इस प्रकार के कई कानून बनाए, जिनका बहुत दुरुपयोग हुआ। अब जो कानून आप बनाने जा रहे हैं मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इस कानून का भी बेतहाशा दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग के बाद मंत्री जी, पुन: आप संशोधन के लिए तैयार रहिएगा। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आपको यह बताना चाहते हैं कि इसका बहुत अधिक दुरुपयोग होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

श्री अरविन्द कुमार सिंह: तलाक के बाद हमारी मां को, हमारी बहन को सम्मान मिले, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होगा, तो उसको रोकने के क्या उपाय किए जाएंगे, इस पर भी आप गम्भीरतापूर्वक विचार कर लीजिएगा।

समय कम है, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाए कि इस कानून के माध्यम से अलग हुए दम्पत्ति को लाभ मिले। ऐसा न हो कि एक को तो लाभ मिले और एक को बहुत ज्यादा नुकसान हो। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपने सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय समाजवाद।

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I rise to support this Bill. Today, many of them here are concerned and worried about women misusing this Bill. I really can't understand that when it comes to a women's Bill, the first point, that is always raised, is that women will misuse it. Even here, somebody was talking about dowry cases. Now, we have heard of so many dowry deaths, so many women being burnt to death, acid injections being put, etc. So much is happening, and still, misuse and women using it as revenge against husband and mother-in-law is the only concern that we have! This is the kind of attitude that we have. My colleague, Shri Derek O'Brien, also spoke about a gender-neutral Bill. Of course, we all welcome a gender-neutral Bill when our country becomes equal, when it gives equal rights to women. I don't think this House, actually, has a right to pass any Bill about women because I can, hardly, see women here. When it becomes 50 per cent,–we have been fighting for 33 per cent–when we have achieved 50 per cent, then, we can talk about women's empowerment and gender-neutral things. Now, we have to be more concerned about the section of the society which is being oppressed, which is not being treated fairly and which doesn't get justice. Sir, this Bill is really progressive and I welcome the Minister for including adopted children along with minor children.

But there are certain concerns which I would like to raise here. It is not very clear when it comes to maintenance. Every time when there is a divorce case and it goes to the court, it is completely left at the mercy of the judge. There is nothing clear. There are no standards to be followed that, for sure, a woman or her children will get a particular portion as maintenance and alimony. In so many cases there is a maintenance or an alimony awarded but there is no mechanism put in place that it

should be paid every month or whatever the time interval is. If it does not come then, most of the women here do not have the choice to choose what they want to do or to choose the kind of education they want to have and they don't have the right to choose what kind of careers they want to pursue after marriage or before marriage. Everything else is restricted and you cannot expect a woman to be completely free to make economic decisions. That kind of right is not there. So, in this case, she completely depends on her spouse for her income or maintenance. We have to put in place a mechanism to make sure that it reaches her and her children properly. It is mentioned that minor children, unmarried girls and widowed daughters will continue to get the maintenance. At 18, many of the boys also have not finished their education. We also have to take care of their rights.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: About ancestral property, it has been mentioned that it will be decided in court. The value of the ancestral property will be decided in court and there will be a ruling on that. But I think, that also is very ambiguous. It leaves a lot of space for different kinds of interpretation in different cases. I think, we have to have something clear about maintenance in this Bill. Thank you.

SHRIMATI RENUBALA PRADHAN (Odisha): Respected Sir, I am grateful to you for allowing me to participate and share my views on the Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I support this Bill which is brought for consideration before this august House. The Marriage Laws (Amendment Bill, 2010) has been brought before this House to further amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954. As part of the Hindu Code Bill, the Hindu Marriage Act was enacted in 1955 by the Indian Parliament. It is an Act to amend and codify the marriage laws among Hindus. Its purpose was to regulate personal life of Hindus, especially the institution of marriage, its validity, conditions for invalidity and applicability.

Sir, on the demand from various quarters for making irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce under the Hindu Marriage Act, 1955, the Central Government referred the matter to the Law Commission of India for its consideration. The Law Commission, in its 71st Report titled, "The Hindu Marriage Act, 1955– Irretrievable Breakdown of Marriage as a Ground of Divorce" submitted in April,

[Shrimati Renubala Pradhan]

1978 had examined the issue in detail and recommended amendments to the Hindu Marriage Act, 1955. Sir, based on the recommendations of the Law Commission, a legislation was proposed. The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010 to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954, by making divorce easier on ground of irretrievable breakdown of marriage, was introduced in the Parliament in 2012. The Bill replaces the words "not earlier than six months" in Section 13B with the words "upon receipt of a petition." It also provides a better safeguard to wife by inserting Section 13D by which the wife may oppose the grant of a decree on the ground that the dissolution of the marriage will result in...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRIMATI RENUBALA PRADHAN: ...grave financial hardship to her and that it would in all the circumstances be wrong to dissolve the marriage.

The new Section 13E provides restriction on decree for divorce ... (time-bell)...affecting children born...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is over.

SHRIMATI RENUBALA PRADHAN: ...out of wedlock and states that a court shall not pass a decree of divorce under Section 13C unless the court is satisfied that adequate provision for the maintenance of children born out of the marriage has been made consistently with the financial capacity of the parties to the marriage.

With these words, I support the Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am calling the next speaker. Mrs. Vandana Chavan.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I stand to support the Marriage Laws (Amendment) Bill, but I do so with mixed feelings. On the one hand, this Bill puts at rest a long-pending direction from several quarters—the hon. Supreme Court and the Law Commission Reports—to make irretrievable breakdown of marriage a ground for divorce.

Matrimonial relations are matters of delicate human and emotional relations. When they are broken, it is impossible for them to make up and it is useless to wash

dirty linen in public and, through 13B and 13C, naturally, this is, now, circumvented.

Realizing that I have a very few minutes at my disposal, I would like to say that there are several welcome provisions. The most welcome provision in this Bill is that the maintenance and upkeep of wife and children have been given supreme consideration while granting divorce under Section 13C.

Sir, I wish to air my concern. That is, we have to realize that the families are now becoming more and more democratic and more egalitarian. Women, as mentioned by several of my colleagues, in some cases, are earning as same as their husbands and in some case even more. While this Bill gives an opportunity to oppose the irretrievable breakdown of marriage for women, it is unfair that, under this Bill, a man cannot at all challenge a divorce petition filed by his wife. It may sound odd for a woman saying this. But, just as it is important that we fight for women's cause, I think, it is very important that we also fight for human rights which may be even more important. There is no doubt that women have suffered for centuries. So, we have to be protected and our children have to be protected. But that is no excuse to make the current generation of men suffer. In this case, I would like to substantiate my argument by inviting the hon. Minister's attention to the Law Commission Report No. 217. While making its recommendations in the last para 3.1, it recommended that immediate action be taken to introduce an amendment to the Hindu Marriage Act and the Special Marriage Act for inclusion of irretrievable breakdown of marriage as another ground for grant of divorce which we are doing now.

Sir, para 3.2 specifically says that the amendment may also provide that the court, before granting the decree of divorce on the ground that the marriage has been irretrievably broken down, should examine whether adequate financial arrangements have been made for the parties and children.

However, para no. 5 of the Statement of Objects and Reasons of this Bill, unfortunately, only says 'subject to certain safeguards to wife and affected children.' Now, Sir, the Commission talked about 'parties' and 'children.' My colleagues, Mr. O'brien and Smt. Kanimozhi also voiced this. Of course, women need justice. But, it should be a gender neutral provision.

Thank you.

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Sir, I do not know how much time you have allotted to me, but I would say that to bundle out such an important Bill in such a short period is not just. You should allow enough time for deliberations in this House. Having said so, I would try to confine myself to the time given to me.

This Bill has a very good intention and, therefore, I would like to thank the hon. Minister for having brought forward this Bill. But, Sir, in today's modern society—we are living in the 21st century—every enactment should be gender-free and religion-free. Here, we should have been gender-neutral and religion-neutral. However, this Bill seems to be taking only the women into consideration. Also, it relates only to the Hindu marriage. I do not understand why this Government should keep a divide between the different religions even in this 21st century. This Bill is called the Marriage Laws (Amendment) Bill, but actually, it is the Hindu Marriage Laws (Amendment) Bill. As Dr. Najmaji has specifically mentioned, women belonging to other religions should also be covered under this law. That is also very necessary. In the same way, the expression 'spouse' should have been used instead of 'husband' because that would have sounded more just because many a time, a woman earns more than the man. What about the maintenance in such cases? There would be many litigations because of this.

There is another thing, Sir. I fear that because of the provisions in the Bill, many broken marriages would remain intact only on paper. The woman would be deprived of the right to get separated and remarry, because if there is a provision for inheritance of property, many families would think 'why give divorce, why allow her separation, let her remain in the family'. They would carry on then and, in that case, you would be depriving a woman the right to get separated. I think, the Minister, who is an eminent lawyer, should look into it very carefully and do the needful in this case. Though I say that this Bill is good, the right to challenge the divorce should remain equal. If a woman intends to challenge the divorce, then, even the man should also be able to challenge the divorce, because it is a mutual thing. Marriage does not belong to one party; a marriage is between two parties. When they are separating, they should be given equal rights for separation.

Therefore, Sir, I believe that the Minister would take into consideration all these nitty-gritty, because there is a very thin line between what could be just and

what is not just. You should look at the grey areas which could be interpreted differently. For Parliament, it is just a matter of passing or not passing a Bill, but if we are adding to the problems of every woman and man, who undergo the pain of getting separated, then I think the whole purpose is defeated.

Then, Sir, issues have been raised about their dependent children. As has been said here, some cases might involve an 18 year old boy or an 18 year old girl who may not even have completed his or her education. So, how do we define it for them? I think, even there we need to have some clarity in the definition so that it would not be unjust to any of the persons concerned. Thank you, Sir.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Thanks your honour. I am grateful for your kind indulgence. I stand for supporting this Bill, which is a progressive Bill. I will call it a legislation for liberation of women, a legislation for empowerment of women.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please be short; you have two minutes.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: A legislation which is a kind of Magna Carta for those who are suffering a marriage which becomes a continued torture. When married life becomes hell, जब दाम्पत्य जीवन नर्क बन जाए, then we call it irretrievable ground for divorce.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY) in the Chair].

Madam, four authorities have supported this Bill. Firstly, the Law Commission's 71st Report recommended that it should be done. Secondly, the Supreme Court's judgement of 1985; thirdly, the Supreme Court's judgement of 2006; and, finally, the 18th Law Commission; all of them have unambiguously pointed out that this is the need of the hour. And, hence, this legislation was introduced in the Lok Sabha on 27th February, 1981. It is of 33 years' vintage. देर आयद दुरुस्त आयद। But the hon. Law Minister and the Government has to explain why it took 33 years, if this was considered to be a very important legislation. We would like to hear the views of the hon. Minister on this.

Madam, as far as divorce is concerned, it has been very rightly pointed out, it becomes a मजबूरी only. No woman of her own volition, no woman because of fun,

[Shri Gyan Prakash Pilania]

no woman just because of toss of a coin will go in for divorce. Divorce is a curse for a woman, which she has to accept when there is no way out, and that way out has been suggested in this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Thank you; thank you. Please conclude.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Madam, I will just take a second more. My suggestion is, this should be applicable to all Indians irrespective of their creed, caste, and place. It should not be applicable only to Hindus. Why are other women who are suffering not given this opportunity? So, it should be looked into. It may be beyond the pale of this Act; it may be beyond the purview of the discussion. But this is a point which has been put forth by so many distinguished Members of this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Thank you Pilaniaji. Please conclude. Now, Shri Pyarimohan Mohapatra.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: There should be one law for everyone. There should be one law for every citizen, and one law for every woman. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Please conclude. The next speaker is already on his feet. Thank you.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: I will again say, देर आयद दुरुस्त आयद, and hope that the women will get some relief. Thank you very much, Madam. Thank you for your goodness.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Mr. Mohapatra, please keep in mind the time constraint.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Odisha): Madam, I will go by telegraphic language. First, I agree that this particular law is not for the poor women, the lower middle-class women and the Muslim women. Particularly, I refer to the Muslim women because I have been a witness in a number of Muslim marriages. The amount is so paltry, even the amount given to educated, well-placed couples, that

one wonders what happens to the lady when only that much amount is paid and the lady is gone. What are you doing for that? Madam Heptulla raised that issue and many Members have supported that. Instead of appeasing for vote-bank politics, will you think of them as Indians and do something about it?

Second is irretrievable breakdown of marriage. What is the ground for irretrievable breakdown of marriage? It can be in the hands of the judiciary. The Transparency International has shown 36 per cent corruption in the judiciary. What can happen, please imagine. I have seen so many grounds of divorce with some lawyers, one, 'did not respect my father, so my tension increased; I suffered from blood pressure; there was not enough milk for the child in my breast.' This was the ground, irretrievable ground for divorce. It is very easy to bring a particular term. This is perhaps to make it for rich and professionals. Professionals keep on changing their spouses. This is not going to work in our society. People will misuse it. Regarding mutual consent, now, if you thought that the Standing Committee had done that the old thing is six months, clear six months, think about it coolly. That is about cooling-off period. Why do you again hand it over to the judiciary that it can reduce it? Please, Mr. Minister, do rethink about this before the Bill is passed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Mr. Mohapatra, please conclude. ...(*Interruptions*)... Thank you.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Please amend it. Just a second, Madam. Please amend it to say that the old thing is restored, otherwise, with the corrupt in the judiciary we will have problems. Then, I agree with others that it should be gender neutral and in this 'grave financial hardship, please cut out the word 'grave' because again in the hands of some in the judiciary, it is liable to be misused. It should be 'financial hardship' only and it should be available to both, husband and wife. Wife's property should also come in this. Thank you.

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं विवाह विधि संशोधन विधेयक, 2010 का भावनात्मक रूप से समर्थन करता हूं, परंतु उसमें बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो विसंगतिकारक हैं, तकलीफदेय हैं। महोदया, धरा 13(ख) में यह संशोधन है कि इस के बाद इसे हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ा जाए। भारत के संविधान में समान अधिकार और समान अपराध के लिए समान सज़ा का प्रावधान है। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार यह निर्णय दिया है कि इस देश में समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, लेकिन उस दिशा में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, जिसे उठाया जाना चाहिए।

[श्री थावर चन्द गहलोत]

महोदया, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मध्य प्रदेश की एक मुस्लिम महिला शहबानों ने उसके पति द्वारा तलाक दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि उसके भरण-पोषण की व्यवस्था उसके पति से करायी जाए, जिसने उसे तलाक दिया है। महोदया, दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को व्यर्थ करने के लिए पिछली तारीख से इस संसद ने कानून बानया और उसे वह लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया। आज इस तरह की अनेक महिलाएं हैं, जिनके बारे में आप और हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम मानव अधिकार की बात करते हैं और हम ने मानव अधिकार आयोग भी बना रखा है, परंतु इन सब बातों पर हम विचार नहीं करेंगे तो इन संस्थानों का कोई औचित्य नहीं है। फिर एक बात यह कि सामान्यतः पहले यह कानून बना हुआ था कि अगर पति-पत्नी एक दूसरे को तलाक देना चाहे, तो वे सत्र न्यायालय में अर्जी लगाएंगे और सत्र न्यायालय 6 महीने तक इंतजार करेगा कि वे दोनों फिर से साथ रह सकते हैं या नहीं, उनके संबंध ठीक हो सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, तो उनका तलाक स्वीकार कर लिया जाता था। आप इस में प्रावधान कर रहे हैं कि 6 महीने के बाद और 18 महीने के पहले, तो आपने जो डेढ़ साल की अवधि बढ़ाई है, यह भी कष्टकारक है। फिर इस में एक शर्त डाल दी है कि अगर पति-पत्नी के संबंध खराब हुए और वे तीन साल तक अलग-अलग नहीं रहे और अलग-अलग में भी उसी परिवार में, उसी घर में या परिसर में रह रहे हैं, तो वह मान्य नहीं होगा। उनको घर छोड़कर कहीं अलग रहना पड़ेगा। अगर यह सिद्ध हो जाएगा कि तीन साल तक वे अलग रहे हैं, तभी इस पर विचार होगा, वरना नहीं होगा। इसमें अच्छाई भी है, लेकिन दूसरी ओर यह तकलीफदायक भी है। जब इस प्रकार के तलाक होते हैं और पति और पत्नी का विच्छेदन हो जाता है तो उनसे उत्पन बच्चों की हालत बहुत खराब रहती है। इसमें उनके लिए प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। यह तो ठीक है, लेकिन एक-तरफ निर्णय हो कि केवल पति ही इसकी भरपाई की कोशिश करेगा, यह जो प्रावधान इसमें है, वह कष्टदायक है। मैं इस अवसर पर यह आग्रह करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखकर इस देश में समान नागरिक कानून संहिता बननी चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम में एक ही शादी करने का प्रावधान है। मैंने इस संबंध में कुछ अध्ययन किया है। फिर क्या कारण है कि इस प्रकार की बात हो? हम मुस्लिम वर्ग के हमारे मित्रों से ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): आप संक्षेप में अपनी बात कह दीजिए। कृपया अब कनक्लूड कीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं केवल एक मिनट लूंगा। महोदया, मैं हमारे भाइयों से कहना चाहता हूं कि या तो आप शरियत की बात स्वीकार करो। शरियत के हिसाब से अगर चोरी करने वाले के हाथ काटने का प्रावधान स्वीकार करते हो, तो यहां भी करवा लो। इसी तरह

से अगर कोई किसी के साथ बलात्कार करता है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको कोड़े मारे की व्यवस्था शरियत में है, आप इसको भी स्वीकार कर लो। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मारेंगे और जब तक आप मरेंगे नहीं, वे मारते रहेंगे। या तो आप यह कानून लागू करा लो या भारत के संविधान के अंतर्गत जो कानून हैं, उनको लागू कराओ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): बस, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। श्रीमती गुन्डु सुधारानी।

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए, धन्यवाद।

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Andhra Pradesh): Thank you, Madam, for permitting me to speak on this important piece of legislation, which will have serious ramifications. In the absence of an institutional mechanism for their social security, once the marriage is annulled, the married women would be in a disadvantageous position.

The first point, which I wish to make, is that the Bill proposes to make 'irretrievable breakdown of marriage' as a ground for divorce. But, the definition of 'irretrievable breakdown of marriage' has not been defined anywhere. I would like to know the grounds and the percentage of deterioration of relations that you call as 'irretrievable breakdown of marriage'. In the absence of such a definition, the courts will also find it difficult how a divorce, under the proposed ground, should be granted. So, in order to ensure that the courts follow uniform standards in dealing with divorce petitions, it is necessary to define the phrase 'irretrievable breakdown of marriage'.

Secondly, under sections 13C and 28A, the Law Minister proposes to grant a decree of divorce. I oppose this, as in the absence of an institutional mechanism, these clauses could be misused to deny women and children their rights in property. The clauses, which allow divorce by mutual consent, must be linked to a social security mechanism as well. Otherwise, this gives one more leeway for males to get divorce. I am saying this because most relationships, particularly where women are involved, in our country continue to be unequal. So, I demand that enough safeguards have to be provided in the legislation itself to ensure that women not only get matrimonial property of her husband, but there has also to be a clear stand on the children adopted by the couple.

[Shrimati Gundu Sudharani]

Thirdly, urban women are more intelligent and are aware of their matrimonial rights. But, if you look at the villages, the situation is entirely different. Most of the women do not know that, under the law, they are granted many rights. Even if they do know some rights–such as, right of daughters to inherit a share of their parents' property– they are forced or persuaded to sign away their rights. A recent study by the Rural Development Institute of Women's Land Rights, in Andhra Pradesh and Bihar, noted that more than half the surveyed Hindu women had signed away their right to land, which they would have otherwise inherited, thereby losing their economic security. This one example gives a clear-cut idea about the status of rural women in the country. So, I would like to know from the hon. Minister how he would look at it and come to the rescue of rural women. One more thing, Madam. The proposed Bill is silent on what will happen to the pending cases registered under the Domestic Violence Act, the IPC, the Cr.PC or any other civil and criminal case. I request the hon. Minister to also explain this, Madam.

Finally, the genesis of this Bill is the case, Naveen Kohli *Vs.* Neelu Kohli. It is in this case that the Supreme Court recommended to the Union Government to seriously consider for bringing an amendment to both the Acts. But, it appears that the Government has not understood the basic intention of the Supreme Court. The Supreme Court observed and I quote:

> "Marriage between the parties had broken down irretrievably with a view to restore good relationship and to put a quietus to all litigations between the parties and not to leave any room for future litigation, so that they may live peacefully hereafter....."From a plain reading of the above observation....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Thank you, Sudhaji.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: One more minute, Madam. ..(*Interruptions*)..

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): मैडम, एक घंटे का समय तय हुआ था।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): एक मिनट, अभी वे बोल रही हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: It is very clear that the intention of the highest court was to give relief to both the parties out of a dead marriage so as to close all the pending litigation between parties, so that they can spend the remaining part of their life peacefully. But, unfortunately, the Bill is completely contrary to the intention of the Supreme Court's observation.

With these words, I conclude my observations. Thank you, Madam.

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (Karnataka): Madam, the Standing Committee recommended that you should define the term 'irretrievable breakdown'. But even if we cannot do it exhaustively, I think some illustrative definition will be called for.

Second point is, I find that this legislation is a little anachronistic when you prescribe some time period for staying apart. These days, marriages exist on even people living in different continents. Our own Army Jawans live away for a long period from their families. Do you mean to say that that is a ground for an irretrievable breakdown? On the other hand, in the Muslim law, four wives live under the same roof; the first, second and third wife have already had irretrievable breakdown. So, where is the linkage between staying apart or staying in the same house and breakdown?

The third thing is, there is an inherent contradiction between clause 3 (13 C) and clause 3 (13 D) In clause clause 3 (13 C) , you are prescribing a period of staying apart. In clause clause 3 (13 D), you say that the affected person can cite grounds for grave financial hardships. The very fact that a person has been forced to live three years apart, the other person will come and say, "she has stayed apart for a long time. That means, she is able to look after herself." So, I think there is a contradiction between clause 3 (13 C) and clause 3 (13 D). I think these are some of the points which you have to look into before you pass this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Now, Mr. Minister.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Madam, Mr. Achutan has to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): No, it is not there in the list. I am sorry.

SHRI D. RAJA: Madam, it is there in the list.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Sorry, it is not there in the list. You can discuss it with the Chair. ...(*Interruptions*).. Please let the hon. Minister speak now. ..(*Interruptions*)..

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Madam, please allow me to speak for two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): I don't know if the Minister will yield. I have already called him. Please let him speak.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KAPIL SIBAL): The time allotted was one hour. ...(*Interruptions*)..

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैंने दो मिनट बोलने की रिकवेस्ट की है। ...(व्यवधान)...

†**جناب محمد ادیب** : میڈم، میں نے دو منٹ بولنے کی ریکویسٹ کی ہے --(مداخلت)--

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): मैडम, मुझे भी इस बिल पर बोलना है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Okay. Just a moment. Please sit down. May I please gather my thoughts here and tell you? Yes, Mr. Achuthan, you can speak. I am sorry, that list was different.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Madam, Vice-Chairperson, 'we politicians', 'we' means male politicians, while speaking in public forum, generally, say that we are for equality, equal rights for women and so on, but when it comes to the law-making process, our mindset is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): You have two minutes, Mr. Achuthan. Please be brief.

SHRI M.P. ACHUTHAN: I don't want to use the word 'anti-woman', but we are not ready to give equal rights to women. That is the mindset.The same thing is seen in this process. Even the social media is being used against this Marriage Bill because if this Bill is passed by the Parliament, then, all the rights of men will be lost, women will have an upper hand, and, women will grab all the property. So much of canards are being propagated through social media.

---

†Transliteration in Urdu script.

Sir, apart from it, the first point which I wish to make is that the women must get, the wife and the children must get equal rights to the property which is acquired after marriage because the hard work of the woman also contributes towards acquiring such property.

The second point is, when this Bill was first discussed in this House, I gave a suggestion to the Minister. Sir, we are making this law in 2013 and the Supreme Court has already accepted the concept of live-in relationship. So, people who have not registered their marriage but are living together have to be treated as couples. They may be having property, they may be having children. What will be the rights of those women and children in the property if they are separated? We have to answer that question. The Supreme Court has already accepted this concept. When will we bring in such an important legislation? This time, we have to include it, and, then, only we can do justice to the women, but this is not there in this Bill. Otherwise, this Bill is relatively a progressive one, and, while I congratulate the Minister for bringing forward this Bill, even though it is a delayed one, I would request you to think about giving equal rights to the women, the wife and the children in the property which is acquired after marriage. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Thank you very much. ..(*Interruptions*).. Mohammed Adeeb ji.

श्री मोहम्मद अदीब: मैडम, इस बिल के आने के बाद, मुझे जिस तरह से मैसेजेज मिले, मुझे बड़ी फिक्र हुई कि कोई ऐसा खतरनाक बिल आने जा रहा है, जिससे मेरे हिन्दू भाइयों और बहनो के साथ कुछ ज्यादती होने वाली है। मैं कल से सब लोगों से पूछता रहा और फिर मैंने यह उम्मीद की कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से बहस होगी तो मैं कुछ समझने की कोशिश करूंगा लेकिन मैंने इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी नहीं देखा कि बिल पर एक बात भी नहीं हुई कि असली मसला क्या है? मुझे इस बात की फिक्र हुई कि दूसरे मुल्कों में क्वानीन कैसे हैं? बड़ी अजीब बात कही गई कि मेरी तीन बहनें तीन जगह शादी करती हैं, तो क्यों करती हैं? मैं कहता हूं कि इस मुल्क की यही तो खूबी थी कि अगर कोई क्रिश्चियन से शादी करता है तो चर्च में जाकर शादी कर ले। ...(**व्यवधान**)...

श्री नजमा ए. हेपतुल्ला: मैंने यह नहीं कहा। ...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद अदीब: अगर कोई हिन्दू मंदिर में जाकर शादी करना चाहे तो वहां कर सकता है, लेकिन आपको फिक्र मुसलिम पर्सनल लॉ की ज्यादा थी। ...(**व्यवधान**)... मुझे अफसोस

[श्री मोहम्मद अदीब]

यह है कि यह इतना अहम बिल है और इस पर बहस होनी चाहिए थी। क्या बात है, लोग क्यों इतने मैसेजेज भेज रहे हैं? आज इस पर बहस नहीं हुई। इस पर बहस मेरिट के साथ होनी चाहिए था। मैंने समझा था कि इसमें मेरिट पर बहस होगी, लेकिन मैंने जितना समझा, अपने फाज़िल मिनिस्टर से यह समझा है कि कोई बहुत अच्छा बिल आया है। मैं इसकी हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब बिल आऐ तो उस बिल पर बहस कीजिए। इस मुल्क की यह खूबी है कि हर मजहब के आदमी को अपने ऐतबार से रहने और जीने का सवाल है। आप उसमें आईन का मज़ाक मत उड़ाइए, यह कह कर कि यह आईन खराब हो रहा है। हकीकत यह है कि इस मुल्क में जो जिस मज़हब को फॉलो करता है, उसका प्रोटेक्शन मौजूद है। मैं इस बिल की हिमायत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस पर अच्छे तरीके से बहस होनी चाहिए।

† **جناب محمد ادیب (اُتّر پردیش)** : میڈم، اس بل کے آنے کے بعد، مجھے جس طرح سے میسیجز ملے، مجھے بڑی فکر ہوئی کہ ایسا خطرناک بل آنے جا رہاہے، جس سے میرے ہندو بھائیوں اور بہنوں کے ساتھہ کچھہ زیادتی ہونے والی ہے۔ میں کل سے سب لوگوں سے پوچھتا رہا اور پھر میں نے یہ امید کی کہ جب لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے بحث ہوگی تو میں کچھہ سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں نے اتنا پالیٹیکل اسٹیٹمینٹ کبھی نہیں دیکھا کہ بل پر ایک بات بھی نہیں ہوئی کہ اصلی مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اس بات کی فکر ہوئی دوسرے ملکوں میں قوانین کیسے ہیں؟ بڑی عجیب بات کہی گئی کہ میری تین بہنیں تین جگہ شادی کرتی ہیں، تو کیوں کرتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی یہی تو خوبی ہے کہ اگر کوئی کرشچن سے شادی کرتا ہے تو چرچ میں جا کر شادی کرلے --(مداخلت)--

بحث کیجئے۔ اس ملک کہ یہ خوبی ہے کہ ہر مذہب کے آدمی کو اپنے اعتبار سے رہنے اور جینے کا حق ہے۔ آپ اس میں آئین کا مذاق مت اڑائیے، یہ کہہ کر کہ یہ آئین خراب ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں جو جس مذہب کو فالو کرتا ہے، اس کا پروٹیکشن موجود ہے۔ میں اس بل کی حمایت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس پر اچھے طریقے سے بحث ہونی چاہئے۔

ڈاکٹر نجمہ اے۔ ہیت اللہ : میں نے یہ نہیں کہا --(مداخلت)--

جناب محمد ادیب : اگر کوئی ہندو مندر میں جاکر شادی کرنا چاہے تو وہاں کر سکتا ہے، لیکن آپ کو فکر مسلم پرسنل لاء کی زیادہ تھی --(مداخلت)-- مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ اتنا اہم بل ہے اور اس پر بحث ہونی چاہئے تھی۔ کیا بات ہے، لوگ کیوں اتنے میسیجز بھیج رہے ہیں؟ آج اس پر بحث نہیں ہوئی۔ اس پر بحث میرٹ کے ساتھہ ہونی چاہئے تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ اس میں میرٹ پر بحث ہوگی۔ لیکن میں نے جتنا سمجھا، اپنے فاضل منسٹر کو یہ سمجھا ہے کہ کوئی بہت اچھا بل آیا ہے۔ میں اس کی حمایت کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بل آئے تو اس بل پر

† Transliteration in Urdu script.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Madam, Vice-Chairman, this is grossly unfair on his part. I was in the meeting of Committee on Privileges, which was being presided by hon. Deputy Chairman.

Shri Balbir Punj, Shri Jai Prakash Nadda, all were there in the meeting. Why should he make a comment like this that the Opposition is not taking it seriously because the Leader of the Opposition or Deputy Leader of Opposition have not spoken.

Najmaji is our senior Member. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Najmaji spoke.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Yes, she spoke. ..(*Interruptions*).. Mr. Thaawar Chand Gehlot is the General Secretary of our party. He is a senior MP. Pilaniaji and we ..(*Interruptions*).. We hold all our Members in great esteem. ..(*Interruptions*)..

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair].

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... This Bill had one hour and it has already taken one-and-a-half hours. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We criticize that statement. ...(*Interruptions*)... It was very, very unfair. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to pass this Bill. It had one hour and now it has taken one-and-a-half hours. ..(*Interruptions*)..

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I made a statement which was twisted and reported in the House by another Member. I respect everybody's right to speak in the House, but no one should twist my statement. I said that I have three daughters and if one marries a Hindu, one marries a Muslim and one marries a Parsi – this is what I said; you can look into the records – then what will happen is all the three will be treated differently. I wanted to say it is not the *khoobi*. The thing is that there is discrimination against women. This law is oppressive. ...(*Interruptions*)... It is against the hundred million Muslim women. ...(*Interruptions*)... This law is against the hundred million Muslim women, and I am sorry if you are a Muslim man ...(*Interruptions*)... and not supporting the Muslim women.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ..(*Interruptions*).. You have made your point. ..(*Interruptions*)..

DR. NAJMA A. HEPTULLA: I am very sorry that you are a Muslim man and not supporting the Muslim women. ..(*Interruptions*).. All the Muslim men who are sitting over here are not speaking a word about it. ..(*Interruptions*).. I am very, very sorry ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Madam. That is all. ..(*Interruptions*)..

श्री मोहम्मद अदीब: लेकिन बिल पर बात भी नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ادیب : لیکن بل پر بات بھی نہیں ہونی —(مداخلت)—**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, now Mr. Minister. ..(*Interruptions*).. That is all. ..(*Interruptions*)..

श्री बलविंदर सिंह भुंडर: उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं क्या करूं, आपने अपना नाम पहले नहीं दिया था, आपने अभी नाम दिया है। आपको पहले नाम देना चाहिए था। आप दो मिनट बोलिए। That is the last speaker. No more names, please.

श्री बलविंदर सिंह भुंडर: उपसभापति जी, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह इतना इम्पोर्टेन्ट बिल है, लेकिन आपने इसमें किसी पार्टी को टाइम दिया है, किसी पार्टी को टाइम नहीं दिया है। आपने मुझे टाइम दे दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब हमारे पंजाबी मिनिस्टर हैं। ये जानते हैं कि जो ब्याह है, यह ब्याह कोई ऐसा बंधन नहीं है कि जब मर्जी हुई यह बंधन बंध गया, जब मर्जी हुई टूट गया। यह ब्याह हमारे धर्म पर आधारित एक सिस्टम भी था। इसमें हिंदू धर्म में फेरे होते हैं, मुस्लिम धर्म में निकाह होता है और सिख धर्म में आनंद कारज होता है। जो आनंद कारज होता है, वह हमारे गुरू ग्रंथ साहब के सामने होता है।

उसमें हमारे गुरुओं ने कहा है, "तन पिर ऐह न आखियन, बैठन इक्ट्ठे होय, एक जोत दोय मूर्ति तन पिर कहअन सोय।" यानी जो मैरिज है, हमारे धर्म के मुताबिक दो मूर्तियों को एक होना चाहिए। मिनिस्टर साहब, मैं शॉर्ट में यह कहना चाहता हूं कि जो पहला पार्ट है, वह ठीक है। सब चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ जो इतनी देर से ज्यादती हो रही हे, वह नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां पर तो यह है भी नहीं, क्योंकि सिख धर्म में तो सबसे पहले

†Transliteration in Urdu script.

यह कहा गया है कि, "सो क्यों मंदा आखिऐ, जित जम्मे राजान।" सबसे पहले यह नारा गुरू नानक देव जी ने दिया था। मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह कहना चाहता हूं कि सभी लोगों इस पर चिंता है। जितने भी मैम्बर्स बोले हैं, सभी के इस पर चिंता है। आपने कानून को अच्छी तरह से देखा है, समझा है और आप बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी कानून को बनाने से पहले उस पर कितनी बातों पर गौर करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि क्या सोसायटी को तोड़ना है? हमें प्रोटेक्शन देती है, लेकिन सोसायटी को तोड़ना नहीं है। आज पोजीशन दोनो तरफ इक्वल है। कई दफ़ा लड़की तंग करती है, कई दफा लड़का तंग कर रहा है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो लॉ हैं, उसमें स्पाउस लफ्ज़ डाल दीजिए, ताकि दोनों तरफ की प्रोटेक्शन हो और किसी के साथ ज्यादती न हो। इसके लिए सब लोगों को सोचना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bhunderji, please. ..(*Interruptions*)..

श्री बलविंदर सिंह भुंडर: जैसा कि उन्होंने बोला है, सारे देश से, हरेक के पास मैसेज़िज आ रहे हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून के ज़रिए समाज को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन हमारा फर्ज़ है, यह हमारी ड्यूटी है ...(**व्यवधान**)... और सर ने जो कहा ...(**व्यवधान**)... ऑनरेबल चेयरमैन साहिब ने ...(**समय की घंटी**)... जो कहा है कि हिंदुस्तान एक कंट्री है, यह कानून सबके साथ एक जैसा है, इसलिए इस देश में जो भी कानून हैं, उसको मानना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, that is all. Mr. Minister, please.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am deeply privileged to be here this afternoon and to hear the distinguished Members of this House support this very historic piece of legislation.

Sir, marriage is an act of sanctity, and the foundation of civilised society is based on marriage. And wherever marriage is broken down in other parts of the world, we have seen the disintegration of civil society. I think it is very important for us to remember, especially in the context of our own traditions and our own civilisation, that we, in India, truly believe in the sanctity of marriage, and, therefore, for many, many years, we made it very difficult for parties to the marriage who were disillusioned with each other to go to court and seek divorce. But times have changed. We are in the 21st century. I am very happy to note that more and more women are part of our national march into modernity. I am sure that in times to come, Kanimozhiji, there will be more women in this House, and there will be more women in the other House too. And I pray that that day comes very quickly.

[Shri Kapil Sibal]

Having said that, Sir, this has been a demand that has been pending for a long, long time. There are two judgments of the Supreme Court. I don't want to go into the details. They were referred to by the distinguished Minister who was then introducing this Bill in this House. There is the 217th Report of the Law Commission which also recommended that irretrievable breakdown should be a ground for divorce, an additional ground for divorce. Of course, this particular amendment only deals with irretrievable breakdown of marriage. It doesn't deal with other provisions of the Hindu Marriage Act. The recommendations of the Law Commission and the recommendations of the Supreme Court were in the context of the Hindu Marriage Act. And it is in that context that we have brought this provision and, of course, also in the context of the Special Marriage Act. The two amendments that we are talking about are amendments to the Hindu Marriage Act and amendments to the Special Marriage Act. In other words, people of any religion, if they so choose, can actually get their marriage registered under the Special Marriage Act. The provisions that Najmaji was talking about will apply to them. But we must give that choice to citizens of our country. We can't foist laws. For example, even in this legislation, it protects Hindu custom and usage. There are several customs and usages around the country with respect to marriages which are also protected under the Hindu Marriage Act and even under this piece of legislation. So, if Hindu custom and usage is to be protected, then other customs and usages must also be protected. And if two partners...(*Interruptions*)...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I did not say that you ...(*Interruptions*)... I said bring a legislation which covers all the women. ...(*Interruptions*)... I talked about ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, in your speech you have said, please bring this into this legislation. I can remind you of what you said in this House. But it does not matter. I don't want to score debating points here. I just want to say that two citizens are equal partners. They are entitled to say to each other, no matter which religion they belong to, that 'we will get our marriage registered under the Special Marriage Act.' ...(*Interruptions*).... But if two people choose to get their marriage registered either under the Hindu Marriage Act or want to marry in accordance with their custom and usage, we should respect those individuals.

5.00 P.M.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, फिर ये अलग-अलग कानून क्यों हैं?

श्री उपसभापति: गहलोत जी, आप बैठिए।

SHRI KAPIL SIBAL: I don't want to enter into an acrimonious political debate on this issue. We are on a very narrow issue that we want to include irretrievable breakdown as a ground for divorce. Irretrievable breakdown as a ground for divorce can only take place. Incidentally, this is gender neutral. It is not that husband cannot move the court for irretrievable breakdown of marriage. The husband too can move the court for irretrievable breakdown of marriage. What is not gender neutral is the division of property. What is gender neutral is the application...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ (Odisha): But, Sir, gender neutral...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: Please, Sir, would you allow me to speak? ...(*Interruptions*)... Would you allow me to speak and answer all the doubts of the distinguished Members of this House? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Balbir Punjji, let him finish. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)... Mr. Punj, the Minister is not yielding. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: You are such a distinguished and learned Member. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding, Mr. Punj. ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: You are such a distinguished and learned Member, you should allow me to explain. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is very clear.

SHRI KAPIL SIBAL: If parties to the marriage are living separately for a period of three years and either of them feels that the marriage has completely broken down, they can move the court–either the husband can move the court or the wife can move the court. What is normally done in legislations in respect of marriage is that the women's rights are protected more than the males' rights. The

[Shri Kapil Sibal]

reason is very simple. We are in a patriarchal society. We can make a great debating point in this House, but let us look into our own hearts. Let's look into our own hearts and ask ourselves how we treat our women. Let's look into our own hearts. Let's look around society and see how society treats women. Women are 50 per cent of the population of the world, but they own two per cent of the assets of the world. That's the reality of global civilisation. Ninety-eight per cent of the assets of the world are held by 50 per cent of the population of this world and they are all males. So, let's be clear. These legislations are a message to the community that Members of Parliament are on the side of women in a patriarchal society. That message must go loud and clear to every citizen of this country and it is with this intent that we brought forward this Bill.

Sir, I am very grateful to distinguished Members of this House to have supported it. Some distinguished Members raised the issue of why women shouldn't be given 50 per cent. In fact, that was the original thought that we had that women should be given 50 per cent. But, then, the situation in the home will differ from home to home. There will be homes in which, when property is purchased, it may be purchased in the name of the women or if land is purchased, it is purchased in the name of the women. There are also situations like that. Now, if you give 50 per cent share and say all property is purchased in the name of the women, then the women may say that they will keep this property and they will also have the 50 per cent share. That also is a human situation that we have to deal with. So, ultimately, we must trust somebody. Now, a distinguished Member of this House asked: How can we trust a Judge because the latest Transparency Report says that 36 per cent of Judges are corrupt? How do we trust politicians with laws because the latest survey says that lots of politicians are corrupt? But, we still have to pass laws and we still have to trust our Judges. We trust and hope that this situation will improve and I hope we will bring forward a legislation to that effect in this country so that what happens in the judiciary improves and what happens here also improves. So, I don't think that that can be a premise on which you can decide as to what kind of laws should be passed. The Judge will decide in the facts and circumstances of each case as to how the property should be distributed. The Judge may, in a certain situation, say that the wife will get only ten per cent. The Judge may, in a certain situation,

say that he would give 50 per cent to the wife. The Judge, in a certain situation, may say, as Sections 13D and 13E demand, he would not grant a decree of divorce because the children of the family cannot be protected, the aged parents cannot be protected, the wife cannot be protected and it would lead to such financial hardship for the old parents, the wife and the children that it would not be fair and just to grant divorce. That power is also given to the judiciary, but we must trust the judiciary and in the event of a particular Judge goes wrong, there is a right of appeal. There is a right of appeal right up to the Supreme Court and I do believe that there are enough honest Judges sitting in the hierarchy of courts that they will correct the wrongs that have been committed at an earlier level. So, I think, we should accept that fact and move forward.

There are three basic amendments that we have brought forward. Firstly, in the property acquired during the course of marriage, which is the self-acquired property of the husband, the wife has a share in it. The extent of the share will depend on the facts and circumstances of each case and will be decided upon by the Judge. The wife also has a share in the movables that have been acquired in the course of marriage. When it comes to inherited property or heritable property, the wife has no share in the inherited or the inheritable property and this is answering your point. But, when the amount of compensation is to be fixed, the value of that asset, which is heritable or inherited, which is an immovable property, will be taken into account by the Judge in determining the extent of compensation that will be fixed by the Judge. So, these are the three basic amendments and these are not eight amendments. These are three amendments in the Hindu Marriage Act and three amendments in the Special Marriage Act. The other is only changing the year of the Act and things like that. The other major amendment is that we have seen, in the past, and this has been our experience, couples go to court by mutual consent, and this has to be done after six months of marriage and before 18 months they have to come back to court, and it is only then that the court grants a divorce by mutual consent. We see many a time though the first application is made, the second application is never made because one of the parties backs out. So, that leads to a prolonged litigation even though the marriage is broken down. So, what we have said is that if after six months when the first application is made, three years passed, one of the parties actually do not cooperate, then, the other party can go to court and say that three years have passed, please give me a divorce by mutual consent.

[Shri Kapil Sibal]

So, that is the other amendment that we have brought. These are the only four amendments that we have brought. There is no amendment which works against women or works in favour of men. In any case most of these legislations are pro-women, and I hope and pray that they continue to be so because we must send that message to the society at large.

There are other points that were made by the distinguished Members of the House as if men have no right to alimony at all. We are not touching upon the provisions of the Hindu Marriage Act, or, other legislations under which the men get the alimony. Under Section 25 of the Hindu Marriage Act, men are entitled to alimony. So, it is not as if men are not entitled to alimony. You may not be entitled to property under this ground of irretrievable breakdown but you are entitled to property under Section 25 of the Hindu Marriage Act. So, it is not as if alimony is taken away from you. I think, women are more worried about men than worrying about themselves in the House. Don't worry; we are taking care of both men and women. We are trying to be fair to everybody. I do believe that in essence I have been able to respond to most of the points that have been made by the distinguished Members of this House. I commend this legislation to the hon. Members of this House for passing

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954 be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In clause 2 there are three amendments. Amendment (No.3) by Shri Kapil Sibal. Then Amendment (No.9) by Dr.T.N. Seema. Then Amendment (No.16) by Shrimati Jharna Das Baidya.

Clause 2–Amendment of Section 13B

DR. T.N. SEEMA (Kerala): Sir, I move:

That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, in amendment

No. 3, the second proviso be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, I move :

(16) That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, in amendment No. 3, the second proviso be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

SHRI KAPIL SIBAL: I move:

(3) That at page 1, for lines 10 to 14, the following be substituted, namely:-

"Marriage Act) in Section 13B, in sub-section (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that on an application being made by both the parties, the court may reduce the period specified under this sub-section to a lesser period and the court may waive off the requirement for moving the motion by both the parties, if it is satisfied that the parties to the marriage are not in a position to reconcile their differences.

Provided further that where one of the parties fails to appear before the court within a period of three years from the date of presentation of the petition under sub-section (1), the court may, on an application made by the other party, waive the requirement of moving the motion by both the parties."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 3 there are six amendments. Amendment (Nos. 4 and 5) by Shri Kapil Sibal. Amendment (No.10) by Dr. T.N. Seema. Amendment (Nos.13 and 14) by Shri M. Rama Jois and Amendment (No.17) by Shrimati Jharna Das Baidya.

Clause 3–Insertion of new sections 13C, 13D and 13E

DR. T.N. SEEMA : Sir, I move:

(10) That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, *for* amendment No. 5, the following be *substituted,* namely:-

"13F.(1) Without prejudice to any custom or usage or any other law for the time being in force, the court, shall, in any proceeding for divorce or separation, on a petition made by the wife, order that the movable and immovable property acquired during the subsistence of marriage be divided equally between the husband and wife.

Provided that the court shall also take into account any disadvantage suffered by the woman or the children with her and give her a further share of the property.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment (Nos.13 and 14) by Shri M. Rama Jois, are you moving your amendments?

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): I want to move my amendments. While moving my amendments, I want to speak about it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You move your amendments.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): What is the fun of giving notice for moving amendments without my views being expressed? If you don't give me an opportunity to express, I am helpless.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, इनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... बिना बोले वे कैसे ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, ...(**व्यवधान**)... यह तो एक नयी परम्परा हो जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ठीक है। आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... But, be brief.. (*Interruptions*)... If you want to speak, be brief. You can give clarification. You can't speak long.

SHRI M. RAMA JOIS: I move:

(13) That at page 2, *after* line 6, the following proviso be *inserted,* namely:-

"Provided that no such petition shall be entertained if the parties to the marriage have children who are of less than fourteen years of age".

(14) That at page 3, *after* line 3, the following be *inserted*, namely;-

"13F. If the petition for divorce is under section

250 of 1955. 13B or 13C of the Hindu Marriage Act, 1955 or under

43 of 1954. section 28A of the Special Marriage Act, 1954 filed by the wife or husband, the spouse as well as children born to them shall have the right to oppose the petition on the ground that it is injurious to their interest, their well being including health, growth, development and education" .

Now, this "irretrievable breakdown" is such a vague term. Both husband and wife on a small quarrel can come and move the petition for divorce. In fact, the marriage bond which comes into existence between the husband and wife itself is irretrievable.

Now they want to say breakdown is irretrievable. I think this is totally inconsistent to the concept of marriage in our culture. Really speaking, it is destructive of family and interest of children. That is why I have moved an amendment to this effect, if there are children below 14 years. The RTE Act has been amended and up to 14 years children have got a fundamental right to education and parents are under obligation to educate them up to 14 years. Therefore, if there are children below 14 years, whether the husband presents the petition, or wife presents the petition, such the petition should not be maintainable. This is one amendment. Secondly, under this law, only wife can oppose. That is totally against the principle of natural justice. Why not husband? If there are children, if they want to oppose the divorce petition, they must have the opportunity to oppose and give valid reasons for that. That is not there. The second amendment is, the opportunity for the husband as well as the children. They must have the opportunity to oppose a divorce petition.

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 13 and 14) by Shri Rama Jois to vote.

The questions were put and the motions were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Amendment (No. 17) by Shrimati Jharna Das Baidya. Are you moving?

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Yes, Sir. I move:

That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, *for* amendment No.5, the following be *substituted*, namely:-

"13F.(1) Without prejudice to any custom or usage or any other law for the time being in force, the court, shall, in any proceeding for divorce or separation, on a petition made by the wife, order that the movable and immovable property acquired during the subsistence of marriage be divided equally between the husband and wife.

Provided that the court shall also take into account any disadvantage suffered by the woman or the children with her and give her a further share of the property:

The question was put and the motion was negatived.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That at page 2, line 46, *after* the words "minor children", the words "including adopted children" be *inserted*.

That at page 3, after line 3, the following be inserted, namely;-

"13F.(l) Without prejudice to any custom or usage or any other law for the time being in force, the court may, at the time of passing of the decree under section l3C on a petition made by the wife, order that the husband shall give for her and children as defined in section l3E, such compensation which shall include a share in his share of the immovable property (other than inherited or inheritable immovable property) and such amount by way of share in movable property, if any, towards the settlement of her claim, as the court may deem just and equitable, and while determining such compensation the court shall take into account the value of inherited or inheritable property of the husband.

(2) Any order of settlement made by the court under sub-section (1) shall be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the husband.".

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are three Amendments; Amendment (No. 6) by Shri Kapil Sibal, Amendment (No. 11) by Dr. T.N. Seema and Amendment (No. 18) by Shrimati Jharna Das Baidya. Are you moving, Dr. Seema?

Clause 6–Amendment of Section 28

DR. T.N. SEEMA : Sir, I move:

That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, in amendment No.6, the second proviso be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, I move:

That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, in amendment No.6, the second proviso be deleted.

The question was put and the motion was negatived.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

6. That at page 3, *for* lines 13 to 17, the following be *substituted*, namely:-

'Marriage Act), in section 28, in sub-section (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that on an application being made by both the parties, the court may reduce the period specified under this sub-section to a lesser period and the court may waive off the requirement for moving the motion by both the parties, if it is satisfied that the parties to the marriage are not in a position to reconcile their differences:

[Shri Kapil Sibal]

Provided further that where one of the parties fails to appear before the court within a period of three years from the date of presentation of the petition under sub- section (1), the court may, on an application made by the other party, waive the requirement of moving the motion by both the parties."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there are three Amendments; Amendments (No. 7 and 8) by Shri Kapil Sibal and Amendment (No. 15) by Shri M. Rama Jois.

Clause 7–Insertion of New Sections 28A, 28B AND 28C

SHRI M. RAMA JOIS: Sir, I move:

1. That at page 3, *after* line 23, the following proviso be *inserted,* namely.-

"Provided that no such petition shall be entertained if the parties to the marriage have children who are of less than fourteen years of age".

The question was put and the motion was negatived.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That at page 4, line 14, *after* the words "minor children", the words including adopted children" be *inserted*.

That at page 4, *after* line 19, the following be *inserted*, namely;

"28D.(1) Without prejudice to any custom or usage or any other law for the time being in force, the court may, at the time of passing of the decree under section 28A on a petition made by the wife, order that the husband shall give for her and children as defined in section 28C, such compensation which shall include a share in his share of the immovable property (other

than inherited or inheritable immovable property) and such amount by way of share in movable property, if any, towards the settlement of her claim, as the court may deem just and equitable, and while determining such compensation the court shall take into account the value of inherited or inheritable property of the husband.

(2) Any order of settlement made by the court under sub-section (1) shall be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the husband.".

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up clause 8. There are two Amendments. Amendment (No.12) by Dr. T.N. Seema and Amendment (No.19) by Shrimati Jharna Das Baidya. Are you moving your amendments?

Clause 8–Amendment of section 40A

DR. T.N. SEEMA : Sir, I move:

That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, *for* Amendment No.8, the following be *substituted,* namely:-

"28D.(1) Without prejudice to any custom or usage or any other law for the time being in force, the court, shall, in any proceeding for divorce or separation, on a petition made by the wife, order that the movable and immovable property acquired during the subsistence of marriage be divided equally between the husband and wife.

Provided that the court shall also take into account any disadvantage suffered by the woman or the children with her and give her a further share of the property:

The question was put and the motion was negatived.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, I move:

That in the List of Amendments dated the 2nd August, 2013, *for* amendment No.8, the following be *substituted,* namely:-

"28D.(1) Without prejudice to any custom or usage or any other law for the time being in force, the court, shall, in any proceeding for divorce or separation, on a petition made by the wife, order that the movable and immovable property acquired during the subsistence of marriage be divided equally between the husband and wife.

Provided that the court shall also take into account any disadvantage suffered by the woman or the children with her and give her a further share of the property:

The question was put and the motion was negatived.

Clause 8 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up clause 1. There is an amendment (No.2) by Shri Kapil Sibal.

Clause 1–Short Title and Commencement

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That at page 1, line 4, *for* the figure "2010", the figure "2013" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause–1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up the Enacting Formula. There is one amendment (No.1) by Shri Kapil Sibal.

Enacting Formula

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty- first", the word "Sixty-fourth"

be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was proposed.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, in the final reading of the Bill, I just want to clarify one point from the hon. Minister. In the original provision, clause 13 (2), it has been stated that three years living separately is a pre-condition to determine that the marriage has broken irretrievably. Now, by an amendment, you are reducing that period.

SHRI KAPIL SIBAL: That is on the mutual consent part. This is on the irretrievable breakdown of marriage part.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Kindly listen to me. Look at your amendment to clause 13B. You are adding two provisos. In the first proviso, you are saying that a period lesser than three years can also be considered by the court. And in the second proviso, you are saying that if an application is moved, even before three years, by one of the parties that one of the parties is avoiding the court, then, the court can grant that.

SHRI KAPIL SIBAL: There are two separate issues. One is for the purposes of irretrievable breakdown and the other is for the purposes of mutual consent.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: My only problem is that it is all there in one amendment.

SHRI KAPIL SIBAL: That may be so. But that is the way it is.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: But, in law, I suppose, it will be reflected separately.

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, of course.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I suppose that is clear now. Now, the question is:

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER–ContdÞ

Mumbai Gangrape Case

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have the statement by the Home Minister. Shri R.P.N. Singh will lay the statement on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Sir, I lay the statement on the Table of the House.

Sir, in a shocking incident, on the evening of 22nd August, 2013, a young lady photojournalist, aged around 22 years, was waylaid and gangraped by a group of men in the abandoned Shakti Mills Compound in Lower Parel, South Mumbai. As per the information available with the police, the young photojournalist, along with a male companion, went for a photo shoot to the mill compound at about 18:00 hours. There, they were accosted by a group of men, who restrained them and then separated them. Thereafter, the lady was gangraped. Later on, both, the lady photojournalist and her male companion, were allowed to go at about 19:00 hours. They reached the Jaslok Hospital, Mumbai, at about 20:00 hrs where the lady photojournalist is being treated.

On receipt of the information by the Police at 20:30 hrs. a gang-rape case was registered in N.M. Joshi Marg Police Station, Mumbai and investigation was initiated. The statement of the male companion has been recorded. Medical and forensic examination has been carried out. Spot visit and collection of evidence from the spot has been conducted. The male companion has provided some vital clues about the culprits and, based on that, the Mumbai Police prepared and released